आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)

बुधवार 24.09.2025 समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- प्रदेश में 1 अक्टूबर से खरीफ फसलों की खरीद शुरू की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने फसलों की खरीद के 72 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
- रेलवे आगामी त्योहारों के दौरान बारह हज़ार विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा।
- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवा पीढ़ी के लिए लाइव कॉन्सर्ट इकोनॉमी कार्यक्रम जल्द आयोजित करने की घोषणा की।
- प्रदेश में भूस्खलन की समस्या के समाधान के लिए एक पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया जाएगा।
- और... आगामी त्यौहारों को देखते हुए, राज्य में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू।

खरीफ फसल

प्रदेश में 1 अक्टूबर से खरीफ फसलों की खरीद शुरू की जाएगी। देहरादून में आयोजित बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने फसलों की खरीद के 72 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती आर्या ने कहा कि सरकार ने धान और मंडुआ खरीद के लिए 600 करोड़ का बजट आवंटित किया है। उन्होंने बताया कि इस साल प्रदेश में धान खरीद का लक्ष्य 7.50 लाख मीट्रिक टन और मंडुआ खरीद का लक्ष्य 5000 मीट्रिक टन तय किया गया है। इस साल गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 हजार 3 सौ 69 रुपये प्रति क्विंटल और मंडुआ का 4 हजार 8 सौ 86 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।

रेल

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि यात्रियों की सुविधा के लिए दीपावली और छठ पर्व के दौरान बारह हज़ार विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई जाएँगी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये विशेष रेलगाड़ियाँ पहली अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच चलेंगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष दिवाली और छठ पर्व के दौरान सात हज़ार 750 विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई गई थीं। उन्होंने कहा कि रेलवे के 29 मंडलों में 90 प्रतिशत गाड़ियां समय से चल रही हैं।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने '71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार' समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' को प्रोत्साहन मिल रहा है।

उन्होंने बताया कि अब भारत ने फिल्म इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाले सभी इक्विपमेंट्स को देश में ही बनाने का लक्ष्य तय किया है, जिससे फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा।

श्री वैष्णव ने यह भी घोषणा की कि युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा लाइव कॉन्सर्ट इकोनॉमी कार्यक्रम जल्द आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्यों के बीच मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशन रूल्स निर्धारित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस

10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत अल्मोड़ा जिले के रैमजे इंटर कॉलेज में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दूर–दूर से आए लोगों ने विभिन्न स्वास्थ्य जाँचें करवाईं और निःशुल्क दवाइयाँ प्राप्त की। शिविर में विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सकों ने आयुर्वेद की विभिन्न विधियों जैसे ईसीजी जाँच, नाड़ी तरंगिनी, मर्म चिकित्सा, न्यूरो थेरेपी आदि से रोगियों का उपचार किया।

इस दौरान जिला आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी डॉ. मोहम्मद शाहिद ने सभी लोगों से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से स्वास्थ्य लाभ लेने का आह्वान किया।

प्रिडिक्शन मॉडल

राज्य में भूस्खलन की समस्या के समाधान के लिए एक पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कल वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान और अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ भूस्खलन न्यूनीकरण के संबंध में आयोजित बैठक में पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने पर जोर दिया।

मुख्य सचिव ने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है जो उपग्रह चित्रों और सतही परीक्षणों के आधार पर किसी विशेष स्थान पर भूस्खलन की संभावना का पूर्वानुमान लगा सके, ताकि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा सके।

बैठक के दौरान, श्री बर्द्धन ने वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान को राज्य की 13 ग्लेशियर झीलों में सेंसर लगाने की ज़िम्मेदारी सौंपी। उन्होंने इन संवेदनशील झीलों की संवेदनशीलता को कम करने के प्रयासों का भी आग्रह किया।

विशेष अभियान शुरू

आगामी त्यौहारों को देखते हुए, राज्य में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों पर, यह अभियान सभी जिलों में एक साथ चलाया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निदेशक डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि दूध और दुग्ध उत्पादों, खाद्य तेल, घी, मिठाइयों, मसालों, आटा, मैदा, बेसन और सूखे मेवों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। निर्माण इकाइयों, थोक विक्रेताओं और परिवहन माध्यमों से नमूने एकत्र कर सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए जाएंगे।

उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नियमित छापेमारी करने और संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशालाओं में भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने मिलावट पाए जाने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

टिहरी जिला पंचायत बैठक

टिहरी की जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवाण की अध्यक्षता में जिला पंचायत सदस्यों ने जिले में आपदा पुनर्निर्माण, कानून व्यवस्था, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में सदस्यों ने अपने–अपने क्षेत्रों की समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान सदस्यों ने जिले में आपदा के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों और पेयजल लाइनों की मरम्मत और लोगों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

आपदा प्रबंधन

बागेश्वर जिले के वज्यूला स्थित अटल उत्कृष्ट पदम सिंह परिहार राजकीय इंटर कॉलेज में चार दिवसीय आपदा प्रबंधन एवं प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी आशीष भटगाईं ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए युवाओं को आपदा प्रबंधन के कौशल सिखाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएँ न केवल छात्रों को जागरूक बनाती हैं, बल्कि उनके गाँवों तथा समाज में भी जागरूकता फैलाने में मदद करती हैं।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर––

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय लिखित भर्ती परीक्षा प्रकरण पर दैनिक जागरण का शीर्षक है– खालिद गिरफ्तार, साबिया सलाखों के पीछे। इस खबर पर हिन्दुस्तान की सुर्खी है– पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी खालिद गिरफ्तार।

बेसिक और जूनियर स्तर के शिक्षकों के लिए टीईटी मुद्दे पर हिन्दुस्तान समाचार पत्र लिखता है– टीईटी पर कोर्ट जाएगी सरकार, जबकि अमर उजाला का शीर्षक है–प्रदेश के 18 हजार शिक्षकों के बड़ी राहत, टीईटी की अनिवार्यता पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार।